

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 20/2022

बउनवान

हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीणा, निवासी रामपुरा भगतान, तहसील मांगरोल जिला बारां राज०

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति :-1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार



(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 23.08.2022

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 30.03.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रामपुरा भगतान तहसील—मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.45 है., किस्म—बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर 720/-रुपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट द्वारा कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2022 निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट  जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।  प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2022 निरस्त फरमाया जावे।

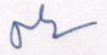
दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 154/2018 निर्णय दिनांक 26.11.2018 से बेदखल किया गया है, जिसकी पुष्टि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय एवं निर्णय की पालना में की गई फर्द जप्ती, बेदखली नामा, फसल नीलामी की छायाप्रतियों तथा पटवारी हल्का के बयान से होती है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न छायाप्रतियां मिसल नम्बर 154/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2018 एवं निर्णय की पालना में की गई फर्द जप्ती, बेदखली नामा, फसल नीलामी से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 140/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारा